

Day-10

1. The Supreme Court's ruling on sub-categorization of SCs and STs ensures fair distribution of reservation benefits but raises concerns over fragmentation within these communities. Critically examine its constitutional, social, and political implications. 8 M

अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करता है, लेकिन इससे समुदायों के विभाजन की आशंका भी उत्पन्न होती है। इसके संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

2. Should a caste-based census be mandatory to ensure reservation policies are evidence-based and equitable? Critically analyze its necessity and role in policy formulation. 8 M

क्या आरक्षण नीतियों को साक्ष्य-आधारित और समानतापूर्ण बनाने के लिए जातिगत जनगणना अनिवार्य होनी चाहिए? इसकी आवश्यकता और नीतिगत भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

3. Tamil Nadu's 69% reservation policy, protected under the Ninth Schedule, faces renewed legal challenges. Discuss the validity of Ninth Schedule protection in light of judicial review and its implications for reservation policies in India. 8 M

तमिलनाडु की 69% आरक्षण नीति, जो संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित है, कानूनी चुनौतियों का सामना कर रही है। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में नौवीं अनुसूची की वैधता तथा भारत में आरक्षण नीतियों पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए।

4. Extending reservation to the private sector is being considered to ensure social justice, but it raises concerns about economic growth and meritocracy. Critically evaluate the feasibility of implementing reservations in private-sector employment in India. 7 M

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इससे आर्थिक विकास और मेरिट प्रणाली को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं। भारत में निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की व्यवहार्यता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

5. The introduction of EWS (Economically Weaker Sections) reservation has sparked a debate over the future of caste-based affirmative action in India. Discuss whether economic criteria should replace caste-based reservations or if a hybrid model is necessary to ensure inclusive development. 7 M

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण की शुरुआत ने भारत में जाति-आधारित सकारात्मक भेदभाव की भविष्य की दिशा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण को जाति-आधारित आरक्षण का स्थान ले लेना चाहिए, या समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल की आवश्यकता है? इस पर चर्चा कीजिए।

